दया राम

बनाम

रघुनाथ और अन्य

15 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाडिया, जेजे.]

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950-धारा 198 (4)-सरकार द्वारा आवंटित भूमि-आवंटन को चुनौती दी गई-आवंटन रद्द कर दिया गया और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा रद्दीकरण को मंजूरी दे दी गई-बिना कोई कारण बताए रद्दीकरण को चुनौती देने वाली रिट याचिका-अपील पर माना गयाः कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के फैसले को टिकाऊ नहीं माना-इसलिए मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया, भूमि कानून और कृषि किरायेदारी।

निर्णय-कारण-आवश्यकता-निर्णय/ऑर्डर-आयोजितः कारण एक क्रम में स्पष्टता का परिचय देते हैं-वे व्यक्तिपरकता को प्रतिस्थापित करते हैं-वस्तुनिष्ठता-यह सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है-प्राकृतिक न्याय के कारणों को स्पष्ट करने में प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

प्रतिवादी संख्या 1 को उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा विवादित भूखंड आवंटित किया गया था। अपीलार्थी (एक सह-ग्रामीण) ने यू.पी. जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 की धारा 198 (4) के तहत इस आधार पर शिकायत दर्ज की कि भूमि का उपयोग पहले मंदिर जाने के लिए मार्ग के रूप में किया जाता थाः प्रत्यर्थी संख्या 1 भूमिहीन व्यक्ति नहीं था और आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और इस प्रकार आवंटन अवैध था। कलेक्टर ने इस आधार पर आवंटन रद्द कर दिया कि आवंटन के लिए अब उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। कलेक्टर के आदेश

के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एक गैर-तर्कपूर्ण आदेश द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी थी। इसलिए वर्तमान अपील पेश की।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कलेक्टर और आयुक्त के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बताया है। एकमात्र कारण अनुलग्नक के संदर्भ में प्रतीत होता है। पूरक हलफनामे के साथ दायर एस.ए.5, जो दर्शाता है कि भूखंड किसी भी तरह से मंदिर जाने वाली सड़क को नहीं जोड़ता है, बल्कि यह मंदिर के पीछे की तरफ है। मूल प्रश्न भूमि के आवंटन के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 की पात्रता के बारे में था। प्राधिकरण के समक्ष विशिष्ट स्थिति यह थी कि प्रत्यर्थी नं. 1 भूमिहीन व्यक्ति नहीं था और इसलिए वह किसी भी भूमि को आवंटित करने का हकदार नहीं था। आदेश में इस पहलू का कोई संदर्भ नहीं है। [पैरा 6 और 7] [1041-एच; 1042-ए-बी]

2.1. कारण किसी क्रम में स्पष्टता लाते हैं। न्याय के बारे में स्पष्ट रूप से विचार करते हुए, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों ने हो, अपने दिमाग के प्रयोग का संकेत देते हुए, अपने कारण सामने रखने चाहिए थे, खासकर तब जब उसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हों कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के फैसले को टिकाऊ नहीं बना दिया है। [पैरा 8] [1042-सी]

ब्रीन वी. समामेलित अभियांत्रिकी संघ, (1971) 1 ऑल ई.आर. 1148 और अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री, (1974) एलसीआर 120, संदर्भित।

2.2. कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर यह है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे" को प्रकट करता है, तो यह अपनी खामोशी से, न्यायालयों के लिए अपने अपीलीय कार्य करना या निर्णय लेने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बना सकता है। निर्णय की वैधता, कारणों का अधिकार एक सुदृढ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कम से कम कारण न्यायालय के समक्ष मामले पर दिमाग लगाने का संकेत देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरूद्ध क्यों गया। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना "स्फिंक्स का अस्पष्ट चेहरा" आम तौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत होता है। [पैरा 9] [1042-डी-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2900/2007।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, यू.पी. के 2003 के डब्ल्यू.पी-1004 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.09.2003 से।

संजय मणि त्रिपाठी, अभय मणि कमल कांत त्रिपाठी और रामेश्वर प्रसाद गोयल अपीलार्थी की ओर से।

श्रीश कुमार मिश्रा, अनीश कुमार गुप्ता, दीप शिखा भारती और रीता गुप्ता उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देते हुए पारित आदेश को दी गई है।

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

16.9.1983 पर उप-मंडल मजिस्ट्रेट, महाराजगंज ने आवंटित विवादित भूखण्ड संख्या 1734 जिसका क्षेत्रफल 0.053 हेक्टेयर है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर आवंटित कियाँ अपीलार्थी एक सह-ग्रामीण, ने देखा कि भूमि का उपयोग पहले काली मंदिर के लिए मार्ग के रूप में किया जा रहा था और प्रत्यर्थी संख्या 1 में सरकार द्वारा किसी भी भूमि को आवंटित करने का हकदार नहीं थाँ भूमि आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पलान नहीं किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 के रूप में भूमिहीन व्यक्ति नहीं था, उसके पक्ष में आवंटन अवैध थाँ अपीलार्थी ने यू.पी. जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 198 (4) के तहत जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज के समक्ष याचिका दायर की। शिकायत मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट ने आवंटन फाइल मांगी और जांच करने पर पाया कि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी और इसे गुप्त रूप से किया गया था। दिनांक 7.11.2002 के आदेश द्वारा, कलेक्टर ने आवंटन को रद्द कर दिया और आगे निर्देश दिया कि भूमि को गाँव सभा द्वारा अपने कब्जे में ले ली जाए। उक्त आदेश से व्यथित प्रत्यर्थी सं. 1 ने गोरखपुर के आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दलील दी थी कि कलेक्टर महाराजगंज द्वारा पारित आदेश अवैध हे, क्योंकि इसमें लेखपाल से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी और कोई स्थल निरीक्षण नहीं किया गया था। आयुक्त ने पुनरीक्षण याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। जनवरी 2003 में, प्रत्यर्थी संख्या 1 उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका सं. 1004/2003 दायर की। प्राथमिक रुख यह था कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा

198 (4) के तहत आवेदन दाखिल करने में देरी हुई थी। प्रारंभ में उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया। अपीलार्थी ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश को अनुमति दी। उक्त आदेश चुनौती का विषय है।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि आदेश तर्कहीन है और इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कलेक्टर और आयुक्त द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप क्यों किया जाना चाहिए। इसलिए आदेश नहीं बनाए रखा दिया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 विद्वान वकील ने कहा कि आदेश में कोई खामी नहीं है।

6. हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कलेक्टर और आयुक्त के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बताया है। एकमात्र कारण इसके साथ दायर पूरक शपथ पत्र अनुलग्नक एसएएस के संदर्भ में प्रतीत होता है, जो दर्शाता है कि प्लॉट संख्या 735 किसी भी तरह से काली मंदिर तक जाने वाली सड़क से नहीं जुड़ता है, बल्कि यह सड़क के पीछे है।

7. मूल प्रश्न प्रत्यर्थी संख्या 1 की पात्रता के बारे में था। भूमि के आवंटन के लिए प्राधिकरण के समक्ष विशिष्ट स्थिति यह थी कि प्रत्यर्थी संख्या 1 भूमिहीन व्यक्ति नहीं था इसलिए, वह किसी भी भूमि को आवंटित करने का हकदार नहीं था। आदेश में इस पहलू का कोई संदर्भ नहीं है।

8. कारण किसी क्रम में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय के स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, अपने दिमाग के प्रयोग का संकेत देते हुए, अपने कारण सामने रखने चाहिए थे, खासकर तब

जब उसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के फैसले को टिकाऊ नहीं बना दिया है।

9. प्रशासनिक आदेशों के सम्बंध में भी लॉर्ड डेनिंग एम. आर. बनाम अमालगेमेटेड अभियांत्रिकी संघ, (1971) 1 एईआर 1148 ने कहा गया है कि "कारण देना अच्छे प्रशासन के मूल सिद्धांतों में से एक है।" अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री, (1974) एलसीआर 120 में यह देखा गया था "कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है। कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग और विवाद के बीच जीवंत संबंध हैं। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर यह है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे" को प्रकट करता है, तो यह अपनी खामोशी से न्यायालयों के लिए अपने अपीलीय कार्य करना या निर्णय की वैधता तय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभ असंभव बना सकता है। कारणों का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कारण कम से कम न्यायालय के समक्ष ममाले पर दिमाग लगाने का संकेत देने के लिए पर्याप्त है। एक अन्य तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके खिलाऊ क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकर आवश्यकताओं में से एक आदेश दिए जाने के कारणों को स्पष्ट करना है। दूसरे शब्दों में बोलना "स्फिंक्स का अस्पष्ट चेहरा" आम तौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत होता है।

10. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपति आदेश को रद्द करते है, मामले को नए सिरे से निपटान के लिए उसके पास भेजते है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। लागत के सम्बंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरजा दाधीच (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।